प्रेस विज्ञप्ति

08 सितंबर, 2016

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

भारत की जनता को मोदी सरकार का उपहार – त्योहारों से ठीक पहले सर्ज प्राईसिंग

मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य– लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई को प्राईवेट हाथों में सौंपकर मुनाफाखोरी

कांग्रेस पार्टी ने यह तुगलकी फरमान फौरन वापस लेने की मांग की

जरूरी वस्तुओं की बढ़ती हुई और खाने पीने की चीजों की आसमान छूती कीमतों के बाद मोदी सरकार ने 'राजधानी, दुरंतों और शताब्दी' ट्रेनों में फ्लेक्सी किराया सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है, जिससे भारत की आम जनता हैरानी में है। दशहरा, दीवाली, छठ पूजा, ओणम, बकरीद आदि त्योहारों से ठीक पहले लिया गया यह फैसला मोदी सरकार की जनविरोधी सोच एवं आम जनता की जेब से मुनाफा कमाने की मानसिकता प्रदर्शित करता है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इन ट्रेनों में एसी 3 टियर, एसी 2 टियर एवं चेयर कार के लिए बेस किराया हर 10% सीटों के बिकने के साथ 10% बढ़ जाएगा और अधिकतम 50% तक बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि टिकटों की मांग बढ़ने के साथ कीमतें भी 1.5 गुना तक बढ़ जाएंगी।

सर्ज प्राईसिंग तब लागू होती है, जब कंपनी मांग बढ़ने के साथ वस्तुओं की कीमतें बढ़ाती है। सर्ज प्राईसिंग का सिस्टम सबसे पहले एप्प आधारित कैब सेवाओं जैसे ओला एवं उबेर ने दिल्ली में शुरु किया था। लेकिन जनता के भारी विरोध के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सिस्टम पर रोक लगा दी थी, क्योंकि आम दिनों में लगभग 13 से 15 रु. प्रति किलोमीटर रहने वाला किराया सर्ज प्राईसिंग में 35 रु. प्रति किलोमीटर तक पहुंच जाता था। इससे बड़े व्यंग्य की बात और क्या हो सकती है कि कोर्ट द्वारा गैरकानूनी करार दिए गए उबेर/ओला सर्ज प्राईसेस का सिस्टम आज मोदी सरकार ने रेलवे में लागू कर दिया है।

रेलवे सर्ज प्राईसिंग का उद्देश्य कुछ और नहीं, अपितु भारत के ईमानदार मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रु. की उगाही करना है, जो रेलवे की कमियों के बावजूद इसे आज भी यात्रा का एकमात्र किफायती साधन मानते हैं। लेकिन मोदी सरकार को अपनी गलती पहचानकर इस 'तुगलकी फरमान' को वापस लेना ही पड़ेगा।

रेलवे को आम जनता की पहुंच से बाहर पहुंचाया– मोदी सरकार ने रेलवे के किरायों में अभूतपूर्व वृद्धि की :

(1) सरकार बनाने के ठीक बाद और रेलवे बजट से कई दिन पहले सरकार ने 20 जून, 2014 को **''यात्री किराए''** में 14.20% एवं **'रेलभाड़े'** में 7% की वृद्धि की थी। नवंबर, 2015

में रेलभाड़ा एक बार फिर 4.35 % बढ़ा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप खाने पीने के सामान सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ीं।

(2) मई, 2014 से 'रेल यात्री किराए' में 20 % की अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी की गई है।

(3) मार्च, 2014 में प्लेटफॉर्म टिकट 100 % बढ़ाकर 5 रु. से 10 रु. कर दिया गया।

(4) दिसंबर, 2015 में तत्काल किराए में 33 % की वृद्धि कर दी गई।

(5) नवंबर, 2015 में टिकट कैंसल करने का शुल्क बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया।

(6) दिसंबर, 2015 तक 16 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 88 लोगों की मौत हुई और 421 लोग घायल हुए।

(7) ट्रैक की सामर्थ्य बढ़ाने, नई ट्रेनें चलाने (जो यूपीए सरकार के समय से लगभग 88% कम हो गया है), सेवाएं बेहतर बनाने और सुरक्षा ढांचे में निवेश करने की जगह सरकार अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रु. का भारी निवेश करने को तत्पर है। इससे साफ है कि सरकार का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी की सनक को पूरा करना एवं विदेशी कंपनियों को ठेका देना है।

(8) सरकार एकतरफा काम करते हुए कॉर्पोरेटाईज़ेशन की आड़ में रेलवे का निजीकरण करने का एजेंडा चला रही है। रेलवे मंत्रालय ने आवश्यक कोड की औपचारिकताओं को पारित करके और सरकार के वित्तीय नियमों (जीएफआर) में बदलाव करके रेलवे की प्राईम रियल इस्टेट प्रॉपर्टी की लूट में कई कॉर्पोरेशनों को लगाया है।

(9) इसी प्रकार ट्रैक का अपग्रेडेशन एवं लोकोमोटिव और कोचों का निर्माण भी कॉर्पोरेशन करेंगी, जिसके लिए सरकार के कुछ पूंजीपति मित्रों को पहले ही चुन लिया गया है।

(10) रेलवे मंत्री ने पिछले बजट भाषण में बड़ी–बड़ी बातें करते हुए कहा था कि 8 से 9 फीसदी की जीडीपी वृद्धि एवं कोयले का परिवहन बढ़ने के आधार पर मालभाड़ा में 850 मीट्रिक टन की वृद्धि तय है, लेकिन सच्चाई यह है कि अप्रैल/दिसंबर, 2014 में मालभाड़ा की वृद्धि सपाट रहकर मात्र 816 मीट्रिक टन ही रही।

(11) जहां रेलवे ने साल 2015–16 में 1,11,852 करोड़ रु. के कलेक्शन का बजट बनाया था, वहीं दिसंबर, 2015 तक कलेक्शन केवल 80,526 करोड़ रु. रहा। देखना यह है कि वित्तसाल के बाकी के महीनों में क्या 30,000 करोड़ रु. से ज्यादा का बचा हुआ कलेक्शन पूरा किया जा सकेगा कि नहीं।